B-244
L-05
Social Justice

## नियोजित विकास (Planned Development)

स्वतंत्रता के बाद भारत में नियोजित विकास पर बल दिया गया और इस दिशा में योजना आयोग का गठन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, विभिन्न मंत्रालयों का गठन आदि के द्वारा नौकरशाही व्यवस्था के सहयोग से प्रयास शुरू किया गया। अन्तिम पंचवर्षीय योजना 2012-2017 तक चली जिसमें तीव्र सतत विकास और अधिक समावेशी विकास पर बल दिया गया।

2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया और 2017 के बाद, पंचवर्षीय योजना को समाप्त करते हुए, नीति आयोग के परामर्श पर विभिन्न मंत्रालयों द्वारा नियोजित विकास को अग्रसारित किया गया।

इस तरह से - स्वतंत्रता के बाद से आज तक विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आर्थिक वृद्धि तथा सामाजिक न्याय को केन्द्र में रख कर विकास की प्रक्रिया क्रियाशील रही है और इसके द्वारा विकास के लक्ष्यों को काफी हद तक प्राप्त किया गया है

[उपलब्धियों की चर्चा करें]।



Scanned by CamScanner

परन्तु -

अभी भी हम अपेक्षित लक्ष्य से दूर हैं और भारत विकास में सामाजिक न्याय के लक्ष्यों को पूर्णतः प्राप्त करने में सफल नही हो पाया है जैसे -

1. आज भी गरीबी एवं आर्थिक विषमता विद्यमान है और समाज का बहुत बड़ा वर्ग निम्न जीवन स्तर एवं भुखमरी का शिकार है।

2. आज भी विश्व विकास में भारत काफी पीछे है और विकास में क्षेत्रीय विषमता, प्रांतीय विषमता, सामुदायिक विषमता, ग्रामीण नगरीय विषमता आदि विद्यमान है।

फलतः क्षेत्रवाद, नक्सलवाद, ग्रवास जैसी समस्याओं का उद्भव हुआ है।

3. आज भी 22.3% (NSO-2023) निरक्षरता के साथ शिक्षा का निम्न स्तर एवं शैक्षिक असमानता (लिंग, जाति, वर्ग आदि के आधार पर) विद्यमान है.

4. स्वास्थ्य विकास के क्षेत्र में, मात्रात्मक एवं गुणात्मक कमी के साथ-साथ, समाज का गरीब तबका आज भी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित है।



Scanned by CamScanner

5. जातीय असमानता एवं लिंग असमानता; आज भी भारतीय समाज के प्रमुख लक्षण बने हैं, और दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, SC, ST, वृद्ध, बच्चे मादक द्रव्य व्यसनी आदि भी, विकास की मुख्य धारा से बाहर हैं और अपवर्जित समूह के रूप में। अति संवेदनशील समाज के रूप में भारतीय समाज में विद्यमान हैं।

6. किसान आत्महत्या, विस्थापन, पर्यावरणीय समस्याएं आदि भी नवीन समस्या के रूप में उभरी हैं जिन्हें विकास जनित समस्या के रूप में देखा जा रहा है।

7. रूढ़िवादिता, परंपरागत मान्यताएं, अस्पृश्यता जैसी सामाजिक बुराईयाँ आज भी भारतीय समाज में विद्यमान हैं।

भारत में विकास नीति एवं विकास कार्यक्रम के अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन से जुड़े मुद्दे / कमियाँ / चुनौतियाँ :-

1. विकास नीति एवं कार्यक्रमों के निर्माण में केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति का होना।

2. विकास से जुड़ी नीतियों एवं कार्यक्रमों के निर्माण में परिस्थितियों, लोगों की आवश्यकताओं एवं सामाजिक मूल्यों पर वैज्ञानिक तरह से विचार



Scanned by CamScanner

का अभाव और भूल सुधार के तर्ज पर विकास नीतियों का निर्माण

3. कार्यक्रम के क्रियान्वयन के स्तर पर कमियाँ/मुद्दे-

3 विकास नीति एवं कार्यक्रमों के निर्माण एवं क्रियान्वयन के पीछे, निश्चित वैचारिकी का अभाव रहा है और चुनाव को ध्यान में रखकर विकास कार्यक्रमों का निर्माण एवं इनका राजनीतिकरण (जैसे- जवाहर रोजगार योजना)

फलतः

- सरकार परिवर्तन के साथ, योजनाओं के प्रति सरकारी उदासीनता एवं उनका नाम परिवर्तन (JNNURM- AMRUT)

  फलतः कार्यक्रमों का टुकड़े में क्रियान्वयन

  फलतः उनका अपेक्षित लाभ न मिल पाना

- कार्यक्रमों का, अन्य कार्यक्रमों में विलय की प्रक्रिया से, विभागीय स्तर पर परेशानी तथा लाभार्थियों में असमंजस

4. विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में केन्द्र एवं राज्य के मध्य परस्पर समन्वय का अभाव



Scanned by CamScanner

और एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप तथा पारस्परिक तनाव एवं राज्य सरकारों द्वारा इन योजनाओं हेतु आवंटित धन को किसी अन्य मदों में खर्च कर देना या बिना खर्च किए केन्द्र को वापस कर देना तथा केन्द्र द्वारा राज्यों के साथ धन के आवंटन में भेदभाव।

5. विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से जुड़ी परंपरागत एवं यांत्रिक नौकरशाही व्यवस्था जहाँ कर्मचारी एवं अधिकारियों में लोकसेवा की भावना का अभाव, संवेदनशीलता का अभाव, लोचशीलता का अभाव, लक्ष्य-उन्मुख के स्थान पर नियम आधारित शासन प्रणाली, लालफीताशाही शासन - फलतः कार्य निष्पादन में देरी एवं गुणवत्ता का अभाव।

6. विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से संबंधित कर्मचारियों एवं अधिकारियों में, दृढ़ इच्छाशक्ति का अभाव, उदासीनता एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षित नहीं होना।

फलतः कार्यक्रमों के प्रति लोगों को जागरूक करके, कार्यक्रमों के बारे में लोगों को परिचित कराकर और कार्यक्रमों में लोगों की सहभागिता / जन-सहभागिता प्राप्त करके उसे



Scanned by CamScanner

सफल बनाने में अक्षम।

7. विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में शामिल विभिन्न एजेन्सियों/क्षेत्रकों के मध्य समन्वय का अभाव।

8. सार्वजनिक जीवन में नैतिकता का ह्रास फलतः भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, जातिवाद आदि फलतः योग्यता की उपेक्षा एवं विकास की प्रक्रिया बाधित।

9. सरकार के पास पर्याप्त पूँजी का अभाव।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR



Scanned by CamScanner